

समाचार पत्रों की कतरने जुलाई, 2025

जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के दौरान उपायुक्त ने दो जानकारों हादसों में घायलों की मदद करने वालों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि

हिमाचल दस्तक | ऊना

ऊना जिले में सड़क हादसों में घायल व्यक्तियों की सहायता करने वालों को अब जिला प्रशासन 25 हजार रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि से सम्मानित करेगा। यह

कहा- 25 जुलाई जानकारी और उपायुक्त बैठक

देकर किया जानकारी ने जानकारी सम्मानित

बीबीएन को आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में दी। उन्होंने बताया कि संबंधित एस्ट्रेपम की अनुशंसा पर यह पुरस्कार राशि जिला रेडबैंस सोसायटी के माध्यम से तकाल प्रदान की जाएगी।

इस पहल का ज्वेश लोगों को सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की



मदद के लिए प्रेरित करना है, ताकि सभी रहते उपचार सुनिश्चित हो सके और अधिक से अधिक जीव बचाए जा सकें। बैठक में उपायुक्त ने सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के पालन को लेकर जननियमकता बढ़ाने के लिए यातायात करने के लिए एक समय सड़क सुरक्षा योजना तैयार करें। उस योजना में यह साफ रूप से उल्लेख हो कि बहाव वर्तमान स्थिति बदल रही है, मुख्य समस्याएं कौन-सी हैं, अब तक क्या सुधार किए गए हैं, और आगे किन उपायों से उन्हें हटाया जाए।

क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा को लेकर नियमित बैठकें आयोजित करें और अधिकारीक बैठकों को सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक एस्ट्रेपम अपने क्षेत्र के लिए एक समय सड़क सुरक्षा योजना तैयार करें। उस योजना में यह साफ रूप से उल्लेख हो कि बहाव वर्तमान स्थिति बदल रही है, मुख्य समस्याएं कौन-सी हैं, अब तक क्या सुधार किए गए हैं, और आगे किन उपायों से उन्हें हटाया जाए।

स्थितियों को बेहतर बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने स्कूल बसों की समय-समय पर जांच और स्कूलों में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता शिविर आयोजित करने के भी निर्देश दिए। उपायुक्त ने हर उपमंडल में प्रमुख स्थलों पर साइनेज, स्पीड ब्रेकर, उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे तथा चैक-चैरों पर ट्रैफिक लाइट लगाने हेतु व्यापक संवेदन कार्यक्रम प्रस्तावित किए। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि यातायात पुरा का गतिशीलता कार्यक्रम प्रगति पहुंच है। उन्होंने डीसी कार्यालय के समीक्षा ऊना-स्पीष्टिकालापुर-सोलोपांड पौक पर शीघ्र ट्रैफिक लाइट स्थापित करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार, अब के बड़ी पौक पर उपायुक्त ऊना-पौक पर साइनेज बोर्ड और ट्रैफिक लाइट की व्यवस्था करने की जाए। ऊना-अब लाइट पर वालों की गति दर्शाने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले यूजिट लगाने तथा गोलार्ड और दैलापुर बाजार सहित अन्य गतराष्ट्रीय स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने को लेकर सभी ओपरेटरों को कहा।

गैहतपुर से ऊना तक एक एक पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे उपायुक्त ने बताया कि गैहतपुर से ऊना-कलापुर एक सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 35 स्थान प्रिवेट किए गए हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि यातायात पुरा का गतिशीलता कार्यक्रम प्रगति पहुंच है। उन्होंने डीसी कार्यालय के समीक्षा ऊना-स्पीष्टिकालापुर-सोलोपांड पौक पर शीघ्र ट्रैफिक लाइट स्थापित करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार, अब के बड़ी पौक पर उपायुक्त ऊना-पौक पर साइनेज बोर्ड और ट्रैफिक लाइट की व्यवस्था करने की जाए। ऊना-अब लाइट पर वालों की गति दर्शाने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले यूजिट लगाने तथा गोलार्ड और दैलापुर बाजार सहित अन्य गतराष्ट्रीय स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने को लेकर सभी ओपरेटरों को कहा।

हिमाचल दस्तक, दिनांक—04.जुलाई .2025

पेज न0-10, कालम—4,5,6,7,8

आरटीओ ने वाहन चालकों को दी सख्त हिदायतें

बीबीएन। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी नालागढ़ विपिन गुप्ता ने स्कूल एवं शिक्षा संस्थानों के प्रबंधन, बस/टैक्सी यनियनों और वाहन चालकों को कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि बरसात में सड़कों की फिसलन, जगह-जगह जलभराव और निर्माणकार्य के चलते दुर्घटना का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे में सभी को अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। आरटीओ विपिन गुप्ता ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों और परिवहन संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाइ जाएगी। उन्होंने वाहन चालकों और मालिकों से आग्रह किया कि वे मॉनसून में विशेष एहतियात बरतें और निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने वाहन चलाते समय फिसलन भरी सड़कों पर रफ्तार नियंत्रित रखें और आकस्मिक ब्रेक लगाने से बचें। उन्होंने कहा कि स्कूली वाहनों को फिटनेस प्रमाणपत्र एवं सभी सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। चालकों के पास आपातकालीन किट, प्राथमिक चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा उपकरण अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहें। उन्होंने सभी वाहन चालकों, स्कूल प्रबंधनों व बस यनियनों से अपील की कि वे विभागीय दिशा-निर्देशों का गंभीरता से पालन करें ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।

हिमाचल दस्तक, दिनांक—04.जुलाई .2025

पेज न0-11, कालम—4

आरटीओ ने की 70 स्कूल बसों टैक्सियों की जांच

शिमला। राजधानी में स्कूली छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आरटीओ विभाग पूरी तरह अलर्ट है। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) शिमला की टीम ने शुक्रवार को ऑकलैंड और ताराहाल स्कूलों के बाहर निरीक्षण किया। विभाग की टीम ने इस दौरान दोनों स्कूलों के लिए संचालित 70 टैक्सियों और बसों के दस्तावेजों की जांच की।

आरटीओ विभाग की टीम दोपहर बाद स्कूल पहुंची। बच्चों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसलिए गाड़ियों को मौके पर नहीं रोका। इस दौरान चालक के लाइसेंस, फिटनेस समेत अन्य जानकारी नोट की गई। आरटीओ ने बताया कि यह निरीक्षण रिकॉर्ड तैयार करने और दस्तावेजों की वैधता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया है। शहर के ढली, भट्ठाकुफर और मल्याण सड़क मार्ग पर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के तहत संचालित तीन गाड़ियों की जांच की। आरटीओ अनिल कुमार शर्मा ने कहा कि स्कूलों के लिए चलने वाली टैक्सियों और बसों के दस्तावेजों की जांच को लेकर अभियान चलाया है। यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। बच्चों की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा। संवाद

हिमाचल में मैनुअल नहीं होगी वाहनों की पासिंग

शिमला। हिमाचल प्रदेश में वाहनों की अब मैनुअल तरीके से पासिंग नहीं होगी। अब ऑटोमेटिक तरीके से वाहनों की फिटनेस जांची जाएगी व उन्हें पास किया जाएगा। राज्य सरकार नादौन व हरोली में ऑटोमैटिक टेस्टिंग स्टेशन बनाने जा रही है। शुक्रवार को इसके लिए 9.57 करोड़ की प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। इसके अलावा 5 करोड़ की राशि भी सरकार ने जारी कर दी है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इसकी पुष्टि की है। इन केंद्रों के बन जाने के बाद वाहनों की पासिंग मैनुअली इस प्रक्रिया को बंद हो जाएगी। परिवहन विभाग प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी इस तरह के ऑटोमेटिक सेंटर तैयार करेगा। बद्दी में भी इसका निर्माण किया जा रहा है। सरकार पांच अन्य स्थानों पर इस तरह के सेंटर बनाएंगी। सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड पर अन्य जिलों में इनका निर्माण करेगी। अभी तक प्रदेश में वाहनों की फिटनेस मैनुअल जांची जाती है। यह ऑटोमेटिक सेंटर विशेष रूप से डिजाइन किया होगा जहां पर इस तरह के उपकरण होंगे कि वाहन को वहां ले जाने पर खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इसमें क्या कमी है।

तारादेवी में 200 गाड़ियों की फिटनेस जांची



तारादेवी में गाड़ियों की जांच करते वाहन निरीक्षक। संवाद

शोधी(शिमला)। सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यशाला तारादेवी के पास वरिष्ठ मोटर वाहन निरीक्षक आज पंकज सिंह ने निजी और वाणिज्यिक गाड़ियों की फिटनेस जांची। निरीक्षण के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। इस अवसर पर जिस गाड़ी में तकनीकी कमी पाई गई उसकी मरम्मत करवा कर फिर से निरीक्षण के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान गाड़ियों के इंजन, जीपीएस ट्रैकर, गाड़ी की लाइट, वाइपर और गाड़ी का प्रदूषण स्तर भी जांचा गया। पूरी तरह से जांच करने के बाद ही फिटनेस प्रमाणपत्र दिया गया। सोमवार को 200 से अधिक गाड़ियों की फिटनेस जांच की गई। इनमें 133 वाणिज्यिक, 31 निजी और 38 नई गाड़ियां थीं। इनमें से अधिकांश गाड़ियां निरीक्षण के बाद फिट पाई गई और उन्हें फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया गया। बाकी गाड़ियों को 16/17 जुलाई 2025 तक उचित मरम्मत करवाकर दोबारा निरीक्षण के लिए बुलाया गया। संवाद

हिमाचल दस्तक, दिनांक—08.जुलाई .2025

पेज न0—2, कालम—1

शिविर में जांचीं चालकों की आंखें

संवाद न्यूज एजेंसी

शिमला। आरटीओ विभाग की पहल पर बुधवार को बस स्टैंड स्थित एचआरटीसी मुख्यालय में नेत्र जांच शिविर लगाया गया। शिविर में 140 ड्राइवर-कंडक्टर और 20 अन्य कर्मचारियों की आंखों की जांच की गई।

डीडीयू अस्पताल से नेत्र रोग विशेषज्ञ टीम ने कर्मचारियों की

आंखों की जांच की और चश्मे वितरित किए। आरटीओ अनिल कुमार शर्मा ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि आगामी विस्तृत परीक्षण के लिए डीडीयू अस्पताल में 10 लोगों को जांच के लिए रेफर किया है।

मौके पर 25 कर्मचारियों को आंखों की दवाई दी गई और आवश्यकता अनुसार उन्हें दवा की अतिरिक्त आई ड्रॉप भी प्रदान किए।

अमर उजाला, दिनांक—10 जुलाई .2025

निजी ऑपरेटरों को राहत देने की तैयारी

शिमला। हिमाचल सरकार निजी ऑपरेटरों को राहत देने जा रही है। बसों में सीटों की क्षमता को कम करने के निर्णय पर सरकारी स्तर पर मथापच्छी चल रही है।

हाल ही में अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी नजीम की अध्यक्षता में परिवहन निगम, विभाग के अधिकारियों और निजी ऑपरेटरों की बैठक हुई थी। निजी ऑपरेटरों ने तर्क दिया कि कई रूट ऐसे हैं जहां निजी ऑपरेटर 42 सीटर बसें चला रहे हैं, लेकिन इनमें सवारियां कम हैं। ऐसे में सीट की क्षमता को कम किया जा सकता है। निजी बस ऑपरेटर संघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेश

विभाग बसों में सीटों की क्षमता को कम करने पर जल्द लेगा फैसला

पराशर ने बताया कि अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन आरडी नजीम में बैठक में इस मामले को सुलझाने की बात कही है।

उधर, शूलिनी निजी बस ऑपरेटर यूनियन के प्रधान रंजीत ठाकुर, कांगड़ा जिला निजी बस ऑपरेटर कल्याण समिति के प्रधान रवि दत्त शर्मा, जिला कुल्लू के प्रधान रजत जमबाल आदि ने कहा कि प्रदेश में बस किराया बढ़ाना समय की मांग है और यह निर्णय सही है। ब्यूरो

अमर उजाला, दिनांक—18 जुलाई .2025

पेज.न0.5, कालम—3,4

सड़क हादसों में मददगार लोगों को मिलेगा इनाम

जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में बोले डीसी शिमला अनुपम कश्यप

हिमाचल दस्तक ■ शिमला

सड़क हादसों में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने वाले मददगार लोगों को

■ गोल्डन ऑवर में पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने पर गिलेंगे 25 हजार रुपये की राशि इनाम के तौर पर दी जाएगी। इसे केंद्र सरकार

की राहवार योजना के तहत दिया जाएगा। साथ ही ऐसे लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा, जो दुर्घटना के गोल्डन ऑवर यानी पहले एक घंटे के भीतर पीड़ित को अस्पताल तक पहुंचाएं।

डीसी शिमला अनुपम कश्यप ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के दौरान ये बात कही।



उन्होंने पुलिस विभाग को ऐसे मददगार नागरिकों की पहचान करने के निर्देश दिये, जिन्होंने बीते दिनों सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद की हो, ताकि उन्हें सम्मानित किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने समिति के सभी सदस्यों से भी ऐसे नागरिकों की सूचना जिला प्रशासन को देने का आग्रह किया, ताकि लोगों को इस योजना की जानकारी मिल सके और लोग ऐसी घटनाएं होने पर दूसरों की मदद करने के लिए आगे आएं। बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी पंकज शर्मा, सहित समिति के अन्य सदस्य और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

हिमाचल दस्तक, दिनांक—18 जुलाई .2025

पेज.न0.5, कालम—3,4,5,6

पुरानी गाड़ी को स्कैप करने पर नए वाहन की रजिस्ट्रेशन में मिलेगी छूट

हिमाचल दस्तक ■ शिमला

हिमाचल में पुरानी गाड़ियों को स्कैपिंग में देने वाले वाहन मालिकों को राज्य सरकार बड़ी राहत देने की तैयारी में है। हालांकि हिमाचल में अभी तक पुरानी निजी गाड़ियों की स्कैपिंग जरूरी नहीं है। मगर इसके बाद भी अगर व्यक्ति अपनी 15 साल पुरानी गाड़ियों को स्वेच्छा से स्कैप करना चाहता है तो उस वाहन

- निजी वाहन मालिकों को राहत देनी राज्य सरकार
- मालिक को स्कैप केंद्र की तरफ से मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट
- मंजूरी के लिए कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा प्रस्ताव

को नए वाहन की रजिस्ट्रेशन में बड़ी छूट प्रदान करेगी। इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार कर दिया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश में निजी वाहनों को स्कैपिंग में देने वाले को रजिस्ट्रेशन में छूट प्रदान की जाएगी। इसके लिए अब केवल मात्र मंत्रिमंडल की

मालिक को नए वाहन की रजिस्ट्रेशन पर छूट प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार स्वेच्छा से 15 साल की अवधि पूरी करने वाले वाहन मालिकों को वाहन स्कैप में देने पर राहत प्रदान करेगी।

राज्य सरकार द्वारा स्वेच्छा से वाहन स्कैपिंग में देने वाले वाहन मालिकों

पुराने वाहनों को हटाने के लिए लागू की है स्कैपिंग सुविधा

उल्लेखनीय है कि सड़कों पर बढ़ रहे डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों की संख्या से पर्यावरण दूषित हो रहा है। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण, सड़क सुरक्षा और वाहन उद्योग के पुनर्विकास के लिए सड़कों पर पुराने और अनुपयोगी वाहनों को सड़क पर से हटाने के लिए पंजीकृत वाहन स्कैपिंग सुविधा लागू की गई है। इसके तहत हिमाचल में भी 15 साल पुराने डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों को स्कैप किया जा रहा है। हालांकि ये पौलिसी केवल सरकारी गाड़ियों पर ही लागू है। मगर इसके बाद भी अगर कोई स्वेच्छा से अपनी 15 साल पुरानी निजी गाड़ी को स्कैप करना चाहता है तो उसे नई गाड़ी खरीदने पर रजिस्ट्रेशन में छूट मिलेगी। कैबिनेट की बैठक ने इसको मंजूरी मिलने के बाद जो निजी गाड़ी मालिक स्वेच्छा से पुरानी गाड़ियों की स्कैपिंग करता है तो उसे राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधा को लाभ मिल पाएगा।

बैठक से मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। जानकारी के तहत इसके लिए पोर्टल तैयार किया जा रहा है। स्कैपिंग के लिए वाहन मालिक को इस पोर्टल पर आवेदन करना होगा। आवेदन के समय पुरानी गाड़ी की कीमत सहित अन्य जानकारी भरनी होगी। इसके बाद वाहन को स्कैप के लिए भेजा जा सकता है। गाड़ी के स्कैप होने पर मालिक को स्कैप केंद्र की तरफ से सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जारी होगा। इसके बाद नई गाड़ी खरीदते पर उसकी रजिस्ट्रेशन के द्वारा राज्य सरकार द्वारा वाहन मालिक को नए वाहन की रजिस्ट्रेशन में छूट प्रदान की जाएगी।

हिमाचल दस्तक, दिनांक—28 जुलाई .2025

पेज.न0.03, कालम—1,2

घायलों की मदद करने वाले 15 अगस्त को होंगे सम्मानित

शिमला। जिले में सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने वालों को जिला प्रशासन सम्मानित करेगा। सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यशाला में सोमवार को उपायुक्त अनुपम कश्यप ने यह बात कही।

उन्होंने बताया कि अभी तक जिला शिमला के जुब्बल के दो लोगों की पहचान हुई है। उन्होंने घायलों की मदद कर अस्पताल पहुंचाया था। बैठक में कहा गया कि इन लोगों को 15 अगस्त को सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर की कमेटी इसकी जांच करेगी। अन्य लोग भी इस तरह के हादसों में घायलों की मदद के लिए आगे आएं। उन्होंने बताया कि चौपाल क्षेत्र में हादसे होते हैं, ऐसे में वहां

पर भी ध्यान दिया जाए। सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यशाला का आयोजन सोमवार को बचत भवन में हुआ। परिवहन, पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य और लोक निर्माण के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में आरटीओ शिमला अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य लोगों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

स्कूल और कॉलेज इसका बेहतर माध्यम बन सकते हैं। शिक्षक बच्चों को गाड़ियों को निर्धारित स्पीड पर चलाने और चिह्नों के बारे में अवगत करवाएं। वर्ल्ड बैंक के अनुसार विश्व में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं भारत में होती हैं। संवाद

सड़क सुरक्षा के लिए सभी विभाग तालमेल के साथ करें काम : उपायुक्त

शिमला में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यशाला का आयोजन

हिमाचल दस्तक | शिमला

शहर में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने की। इस कार्यशाला में पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन विभागों के साथ-साथ जिला प्रशासन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। कश्यप ने कहा कि प्रदेश का मुख्यालय होने के कारण शिमला सड़क सुरक्षा की दृष्टि से विशेष परिस्थितियों वाला जिला है।

इस चुनौतीपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने



की आवश्यकता है। उन्होंने राह वीर योजना की जानकारी देते हुए बताया कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने में सहायता करने वाले नागरिक को 25 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। उन्होंने इस योजना के बारे में अधिक से अधिक जन जागरूकता फैलाने की आवश्यकता

पर बल दिया, ताकि लोग निसंकोच घायलों की सहायता करें और राज्य स्तरीय कार्यक्रमों में उन्हें सम्मानित भी किया जा सके। सड़क दुर्घटनाओं में घायल को बिना किसी अग्रिम भुगतान या औपचारिक प्रक्रिया के सरकारी मान्यता प्राप्त अस्पतालों में 1.5 लाख तक मुफ्त उपचार उपलब्ध कराया जाता है।

हिमाचल दस्तक, दिनांक—29 जुलाई .2025

पेज.न0.03, कालम—2,3,4